क्या सुधा जी इतनी खतरनाक हो गई हैं मोदी सरकार के लिए..... ?

छत्तीसगढ़ के कंपनी मालिक क्यों इनसे डरते हैं ?

आलोक प्रकाश पुतुल, बीबीसी हिंदी डॉट कॉम, साभार

सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली सुधा भारद्वाज के बारे में अगर आप नहीं जानते तो पहली मुलाकात में आप उन्हें कोई घरेलू महिला मान लेने की भूल कर सकते हैं.

यह सादगी उनके घर से दफ़्तर तक हर कहीं पसरी हुई नज़र आती है. लेकिन इस सादगी से परेशान लोगों की फ़ेहरिस्त लंबी है.

अभी कुछ ही महीने पहले की बात है.

छत्तीसगढ़ में एक बहुराष्ट्रीय सीमेंट कंपनी के प्रबंधक ने बातों ही बातों में धीरे से कहा- "नाम मत लीजिए सुधा भारद्वाज का. उनके कारण हमारे यहां काम करने वाले मज़दूर हमारे सिर पर चढ़ गए हैं."

बस्तर में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम को पुलिस के आला अधिकारी ने चेतावनी दी, "अगर आप सुधा भारद्वाज को जानते हैं तो तय मानिए कि आप हमारे नहीं हो सकते."

लेकिन ऐसी राय रखने वालों से अलग छत्तीसगढ़ में कोंटा से रामानुजगंज तक ऐसे हज़ारों लोग मिल जाएँगे जिनके लिए वो सुधा दीदी हैं. शिक्षिका सुधा दीदी, वकील सुधा दीदी, सीमेंट मज़दूरों वाली सुधा दीदी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा वाली सुधा दीदी.

अर्थशास्त्री रंगनाथ भारद्वाज और कृष्णा भारद्वाज की बेटी सुधा का जन्म अमरीका में 1961 में हुआ था.

1971 में सुधा अपनी मां के साथ भारत लौट आईं. जेएनयू में अर्थशास्त्र विभाग की संस्थापक कृष्णा भारद्वाज चाहती थीं कि बेटी वह सब करे, जो वह करना चाहती है.

सुधा कहती हैं, "वयस्क होते ही मैंने अपनी अमरीकन नागरिकता छोड़ दी. पांच साल तक आईआईटी कानपुर से पढ़ाई के दौरान ही दिल्ली में अपने साथियों के साथ झुग्गी और मज़दूर बस्तियों में बच्चों को पढ़ाना और छात्र राजनीति में मज़दूरों के सवाल की पड़ताल की कोशिश शुरू की."

शायद यही कारण है कि आईआईटी टॉपर होने के बाद भी किसी नौकरी के बजाय 1984-85 में वे छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी के मज़दूर आंदोलन से जुड़ गईं.

कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ आना-जाना लगा रहा लेकिन जल्दी ही बोरिया-बिस्तर समेटकर वे स्थायी रुप से छत्तीसगढ़ आ गईं.

दिल्ली राजहरा के शहीद अस्पताल में एक मरीज़ को लेकर पहुंचे कोमल देवांगन बताते हैं, "सुधा और उनके साथियों ने मज़दूरो के बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके कपड़े सिलने तक का काम किया. नियोगी जी ने संघर्ष और निर्माण का जो नारा दिया था, सुधा भारद्वाज जैसे लोग उसे धरातल पर लाने वालों में से हैं."

जुझारू मज़दूर नेता शंकर गुहा नियोगी की 1991 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

शंकर गुहा नियोगी की सचिव रही हैं सुधा भारद्वाज

छत्तीसगढ़ में मज़दूरों के हक़ की लड़ाई में सुधा भारद्वाज उतरीं तो फिर पलट कर नहीं देखा.

शंकर गुहा नियोगी के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को जब एक राजनीतिक दल की शक्ल दी गई, तब सुधा भारद्वाज उसकी सचिव थीं.

लेकिन उसके बाद सुधा भारद्वाज अलग-अलग किसान और मज़दूर संगठनों में काम करते हुए भी पद संभालने से बचती रहीं.

वे आज भी अपने को एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता ही मानती हैं.

छत्तीसगढ़ में सामाजिक संगठनों के समूह "छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन" के संयोजक आलोक शुक्ला कहते हैं, "सुधा दीदी, हमारे जैसे लोगों की प्रेरणास्रोत हैं. वे चुपचाप अपना काम करती चली जाती हैं."

भिलाई में मज़दूरों की लड़ाई हो या एसीसी, लाफार्ज-होलसिम कंपनी के विदेशी प्रबंधकों से लड़ाई और वार्ता का दौर; सुधा भारद्वाज का कहना है कि अधिकांश अवसरों पर सत्ता प्रतिष्ठान की पहली कोशिश हर तरह के आंदोलन को कुचलने की ही होती है. इसके लिए सारे उपक्रम अपनाये जाते हैं.

पूरे छत्तीसगढ़ में मज़दूर आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा खर्चा मुक़दमों पर होता था. मज़दूरों के लिए मुक़दमों की तैयारी में पैसा भी जाता था और मेहनत भी.

40 की उम्र में अपने मज़दूर साथियों की सलाह पर वक़ालत की पढ़ाई कर डिग्री ली और फिर आदिवासियों, मज़दूरों का मुक़दमा खुद ही लड़ना शुरु किया.

मज़दूरों से जुड़े मामलों में फ़ैसले भी पक्ष में आने लगे क्योंकि मज़दूर संगठनों के भीतर काम करने के कारण उसके सारे दाँव पेंच जाने-समझे हुए थे. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऐसे कई मुक़दमे लड़े गए.

कुछ सालों बाद "जनहित" नाम से वकीलों का एक ट्रस्ट बनाया और तय किया कि समाज के वंचित अलग-अलग समूहों के मुक़दमे मुफ़्त में लड़ेंगे.

बिलासपुर के अपने कार्यालय में फ़ाइलों के बीच उलझी सुधा भारद्वाज का अनुमान है कि उनके ट्रस्ट ने पिछले कुछ सालों में कोई 300 से अधिक मुक़दमे लड़े हैं, ज़िला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक.

मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की छत्तीसगढ़ इकाई की महासचिव होने के नाते मानवाधिकार हनन के अलग-अलग मोर्चे पर सुधा भारद्वाज ने कई लड़ाइयां लड़ी.

बस्तर के फ़र्जी मुठभेड़ों की पड़ताल और फिर उसके मुक़दमों ने राज्य सरकार को कई अवसरों पर मुश्किल में डाला.

अवैध कोल ब्लॉक, पंचायत क़ानून का उल्लंघन, वनाधिकार क़ानून, औद्योगिकरण के मसले पर भी सुधा भारद्वाज की ज़मीनी लड़ाई की अपनी पहचान है.

अपनी पूरी संपत्ति मज़दूर आंदोलन में लगा देने वाली सुधा भारद्वाज के पास संपत्ति के नाम पर दिल्ली में मां के हिस्से का एक मकान है, जिसका किराया मज़दूर यूनियन को जाता है.

सुधा भारद्वाज कहती हैं, "संगठन में आर्थिक तंगी तो बनी रही लेकिन हमने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की, अपना मज़दूरों का अस्पताल खोला."

मज़दूरों के मुक़दमें लड़ने वाली "जनहित" भी समान विचारधारा वाले साथियों के चंदे से चलती है. मुक़दमों की ख्याति ऐसी कि मुंबई हाईकोर्ट ने भी हाल ही में छह लाख रुपये "जनहित" को दिए.

सुधा भारद्वाज कहती हैं, "पीछे मुड़ कर देखती हूं तो मैं खुश होती हूं कि मैंने मज़दूरों और आदिवासियों की लड़ाई में थोड़ा-सा साथ दिया. ऐसे लोग, जिनके जीवन में तमाम दुखों के बाद भी मनुष्य होने को बनाए और बचाए रखना पहली प्राथमिकता थी. मैं फिर से ऐसे ही जन्म लेना चाहूंगी, इन्हीं के बीच."

गैरकानूनी और निरंकुश गिरफ्तारियां

मुनेश त्यागी.

सरकार ने वरवर राव, सुधा भारद्वाज गौतम नवलखा ,वरनोन गोन्जालविज आदि प्रगतिशील, जनवादी, दलित और वाम्पंथी कार्यकर्ताओं, वकीलों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, कवियों, लेखकों को गिरफ्तार करके दिखा दिया है वह पूंजिपतियों की राह में आने वाले, किसी भी रोडे और अवरोधों को हटा देना चाहती है. सरकार इन लोगों को अरबन या शहरी नक्सल कह कर गिरफ्तार कर रही है.

जनवादी लेखक संघ मेरठ इकाई इन कानून विरोधी, मनमानी और पूंजिपरस्त कदमों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और सरकार से मांग करती है इन सबको तुरंत रिहा किया जाये.

इन गिरफ्तारियों की आड में सरकार सबको डराना चाहती है, विरोध की आवाज को दबा देना चाहती है, यह सरकार एकदम कानूनविरोधी, संविधान विरोधी, निरंकुश और मनमानेपन पर उतर आई है. वह तर्क या विरोध की आवाज को सुनना ही नही चाहती है. यह किसी पर भी कोई आरोप लगाकर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकती है. सरकार देश को बताये कि उसने किस आधार पर इन वकीलों, कवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुध्दिजीवियों और श्रमिक हितकारियों को गिरफ्तार किया है?

ये गिरफ्तारियां आपातकाल की आहट दे रही हैं, सरकार हर उस आवाज को दबा देने पर आमादा है जो किसानों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों व अनुसूचित जातियों के हितों की हिफाजत करने के लिए उठायी जाती है. अवैध रूप से गिरफ्तार किये गये लोगों का इतिहास बताता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नही किया है बल्कि वे तो किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों दलितों और अल्पसंख्यकों की वाणी है, आवाज है. आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वे भी यही काम कर रहे होते और वे इन सबकी वकालत कर रहे होते.

आज भगतसिंह, बिस्मिल, आजाद, सरदार पटेल और नेता जी सुभाष चंद्र बोस होते तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया होता और गरीबों, कमजोरों, शोषितों और कमेरों की आवाज उठाने की एवज में दंडित किया जाता. सरकार द्वारा की गई ये गिरफ्तारियां एकदम आतंकवादी, डरावनी और निरंकुश हैं, जो कतईभी देशहित में नही हैं और बिल्कुल अमान्य और अमानवीय हैं. हम तो यही कहेंगे.,,,,,,

दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे,
जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया और देखेंगे.

टीवी पर एक राष्ट्रवादी बहस

कृष्ण कांत

एंकर- संबितजी, विपक्ष कह रहा है कि राफेल विमान सौदे में घोटाला हुआ है. आप क्या कहना चाहेंगे ?

संबित- मैं आपके माध्यम से सवा सौ करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूं कि गद्दार कांग्रेसियों ने झेलम के युद्ध में सिकंदर का साथ दिया. बाबर के खिलाफ भी नहीं लड़े. अकबर को सेकुलर बताकर हिंदुओं के साथ दगा की. 1857 के गदर में कांग्रेसी स्विटजरलैंड घूम रहे थे. आजादी के पहले देश भर में हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा था, लेकिन गद्दार कांग्रेसी एक भी दिन शाखा नहीं गए...

एंकर : लेकिन संबित जी...

...मैं बड़ी विनम्रता के कहना चाहता हूं कि आपातकाल लगा तब कांग्रेस अध्यक्ष छह साल के थे, 1984 हुआ तब 14 साल के थे, बोफोर्स हुआ तब 17 साल के थे, लेकिन वे आज ?तक इन सबकी ? जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं. आप देश के लिए हमारा योगदान देखिए. हमने हिटलर की नकल करके गणवेशधारी स्वयंसेवक बनाए, जिन्ना की तर्ज पर 90 साल तक हमने हिंदुओं को गोलबंद करने के लिए शाखा लगाई. अब यह राफेल का सवाल उठाना देश के हिंदुओं का अपमान करना है...

संबित : फिर आपने वही बात की ! क्या आपके चैनल ने देश के हिंदुओं का अपमान करने का ठेका ले रखा है ? क्या आपके चैनल ने... क्या आपके चैनल ने... बैठ जा मुल्ला, बैठ जा पाकिस्तानी... मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहे देता हूं कि हम हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे. मंदिर वहीं बनेगा, वहीं बनेगा, वहीं बनेगा.

स्टूडियो में लाए गए छात्रों की तालियों से संपूर्ण ब्रम्हांड गुंजायमान हो उठा और तर्कशास्त्र ने यमुना के सीवर में कूदकर आत्महत्या कर ली. इतना सुनते देखते ही एंकर अपनी गुप्तरोगनुमा वफादारी पर फूल कर कुप्पा हो गया. डिबेट सुनने वाले भक्तगणों ने अपने मुंह में शरद पूर्णिमा वाला अमृत टपकता महसूस किया और अमरत्व को प्राप्त ?हुए. कांग्रेस के दिग्विजय सिंह यह देखकर सोच में पड़ गए कि हमारे प्रवक्ता भी घोटालों पर इतने ही बेशर्म थे, लेकिन यह इतिहास वाला एंगल हमसे छूट गया था. यह ज्यादा मारक है.

मोदी को हटाने की कवायद और विकल्पहीनता का संकट

मनोज कुमार झा

वर्तमान मोदी सरकार के हर मोर्चे पर फेल हो जाने के बावजूद ऐसा लगता है कि विकल्पहीनता का संकट बना हुआ है। भूलना नहीं होगा कि मोदी विकल्पहीनता के शून्य में ही उभर कर सामने आए थे। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के प्रति लोगों के मन में भारी गुस्सा था। तरह-तरह के घोटालों में सरकार फंसी हुई थी। अर्थव्यवस्था की गति मंद पड़ चुकी थी। वामपंथियों ने बहुत पहले ही सरकार को समर्थन देना बंद कर दिया था। यही नहीं, यूपीए सरकार की विफलता के साथ ही क्षेत्रीय दलों और क्षत्रपों की ताकत में भी कमी आई थी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ाती चली गई। खास बात यह कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा में नये नेतृत्व को उभारना शुरू कर दिया था। आडवाणी जैसे नेताओं को पहले ही ठिकाने लगा दिया गया था। उनके पाकिस्तान जा कर जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने के विवाद ने एक तरह से उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया, यद्यपि वे हिंदुत्व के आर्किटेक्ट माने जाते थे और राममंदिर का आंदोलन चला कर भाजपा को सत्ता में लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। पर संघ के नेतृत्व ने उन्हें किनारे कर दिया और उनकी जगह गुजरात दंगों के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुख्य भूमिका दे दी। इसके पीछे वजह ये रही कि ये बुद्धिहीन और मवाली किस्म के लोग हैं, जबकि आडवाणी पुराने संस्कारों के मर्यादित व्यक्ति हैं, वे खुल कर नंगई पर नहीं उतर सकते थे। पर मोदी और अमित शाह सिरे से मर्यादाविहीन हैं। इनका कोई चरित्र नहीं है। झूठ बोलने और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके अलावा साजिशें रचने में भी ये अव्वल रह चुके हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के सहयोग से जैसा नरसंहार करवाया, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। आजाद भारत में इससे बड़ा दूसरा नरसंहार कोई नहीं हुआ। बहरहाल, इनके इन्हीं गुणों को देखते हुए संघ नेतृत्व ने कमान इनके हाथों में सौंपना सही समझा, क्योंकि आडवाणी जैसे नेता नरेंद्र मोदी के स्तर पर नहीं उतर सकते थे।

यूपीए सरकार के दौरान ही देश के बड़े पूंजीपति जिनमें अंबानी, अडानी और टाटा तक शामिल थे, मोदी से जाकर मिल चुके थे और उनसे प्रधानमंत्री बनने का आग्रह किया था। उन्हें पता था कि कांग्रेस के खिलाफ जैसा जन असंतोष है, उसे देखते हुए सरकार जा सकती है और फिर भाजपा ही सत्ता में आएगी। ये पूंजीपति समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ और बुद्धिहीन है, इसलिए इससे अपने हित के काम कराना आसान होगा, जबकि कोई दमदार व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बना तो वह उनकी हर बात नहीं मानेगा।

इन पूंजीपतियों ने संघ नेतृत्व से साफ-साफ कहा कि यदि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, तभी वे भाजपा को चुनाव जितने के लिए अपना खजाना खोलेंगे। हुआ भी वही। अंदरूनी विरोध के बावजूद संघ ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया और परिस्थितियां ऐसी बनीं कि भाजपा की जीत हुई। मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद इस 'चायवाले' ने जो कारगुजारियां की, वो भला कौन नहीं जानता है। अब सभी त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं। मोदी जहां जाते हैं, तमाशा कर जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। पहले लोग इनकी बातों में आ जाते थे, पर अब सब समझने लगे हैं कि ये आदमी मदारी है, जोकर है, इसके पास अपनी कोई नीति नहीं है, यह सिर्फ अपने पूंजीपति आकाओं के इशारे पर काम करता है। महंगाई, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और अल्पसंख्यकों की जान को हमेशा खतरा देख कर आम जनता किसी भी हाल में भाजपा सरकार और मोदी से मुक्ति चाहती है, पर सवाल है कि कैसे। मोदी को हटा पाना आसान नहीं है। जितनी जनविरोधी ताकते हैं, सब मोदी के साथ हैं। रहा सवाल विकल्प की शक्तियों का, तो वे कहीं भी सरजमीं पर दिखाई नहीं पड़ रहीं। भाजपा के बरक्स कांग्रेस ही राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र पार्टी है, बाकी क्षेत्रीय दल हैं जिनकी हालत अभी बहुत खराब है। तमाम बड़े राज्यों में भाजपा सत्ता में है। आम चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। पर कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों की कोई तैयारी नहीं दिखाई पड़ती। कांग्रेस में ऐसा नेतृत्व उभरता नहीं दिखता जो मोदी को चुनौती दे सके। राहुल गांधी और उनकी मंडली चुनावों के लिहाज से बहुत कमजोर दिखती है। फिर जन असंतोष से मोदी का क्या बिगड़ने वाला है। मोदी और उनकी मंडली रोज ही नये-नये शिगूफे छोड़ कर बुद्धिजीवियों और जनता को भ्रम में डाल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी ने नोटबंदी कर अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई आने वाले दिनों में कोई सरकार नहीं कर सकेगी। रिजर्व बैंक का नोटबंदी को लेकर जो आकलन आया है, उससे साफ है कि यह कितना बड़ा आत्मघाती कदम था। जीएसटी लागू करने से व्यवसायियों को जो नुकसान हुआ है और जितने बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार छिना है, वह भी अभूतपूर्व है। सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसके बारे में सभी जानते हैं। स्वतंत्र भारत में यह पहली सरकार आई है जो हर स्तर पर जनता की दुश्मन है। पर मोदी की जगह कौन, यह है यक्ष प्रश्न। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस अभी तक पता नहीं किस खामख्याली में है और दूसरे दल भी किस कुंभकर्णी निद्रा में डूबे हैं, कहना मुश्किल है। बहरहाल, अगर दोबारा भाजपा सत्ता में आ गई और नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री संघ ने बनवाया तो क्या होगा, इसकी कल्पना भी कर पाना आसान नहीं है। यह कांग्रेस के लिए भी जीवन-मरण का प्रश्न होगा और विपक्ष के लिए भी।